14 अप्रैल 2020

प्रिय साथी,

आशा है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अगली 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ जाने से आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी, लेकिन देश में तेजी से बढ़ रहा कोविद-19 के कहर से बचने का कोई अन्य प्रभावशाली तरीका नजर नहीं आता। इसलिए हमें इसका पूरा पालन करना चाहिए।

इन मुश्किल दिनों में आप में से कई साथी मानव सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं, मैं उन्हें बहुत शाबाशी दे रहा हूँ। बहुत से साथी रात-दिन जुटकर घरों में होने वाले बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ चेतना जगाने का अभियान चला रहे हैं, उनको भी बहुत बधाई।

मैं खुद हर दिन देश और दुनिया के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बात करके बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरों और चिंताओं से उन्हें आगाह कर रहा हूं। मैं भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, श्रममंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, सूचना तकनीक और विधि मंत्री, रेल मंत्री और बहुत से संसद सदस्यों आदि के अलावा दर्जनों प्रमुख उद्योगपतियों से लगातार बातचीत कर रहा हूँ। कई नोबेल पुरुस्कार विजेताओं और विश्व के नेताओं के भी संपर्क में हूँ। दुनिया भर के लगभग एक सौ विशिष्ट लोगों ने जी-20, संयुक्त राष्ट्र संघ और सभी सरकारों से अपील की है कि जल्दी से जल्दी एक बैठक करके स्वास्थ्य की इस आपात स्थिति से निबटने के लिए साहसी वित्तीय फैसले लेकर बड़ी धनराशि का इंतजाम करें ताकि आने वाले वैश्विक आर्थिक संकट को कम किया जा सके। कई राष्ट्राध्यक्षों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुखियाओं के साथ यह पत्र लिखने वालों में मैं भी शामिल हूं।

मैं यह दूसरा लम्बा पत्र आपको कुछ गंभीर मुद्दों पर लिख रहा हूं। आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि इन पर उतनी ही गंभीरता से आपस में और मुझे लिखकर बहस और चर्चाएं करेंगे। क्योंकि महामारी के बाद बदली हुई दुनिया का गहरा और लम्बा असर कमजोर वर्गों, खासकर उनके बच्चों पर पड़ेगा।

1. अभी हमारी प्राथमिकता लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए खुद को और दूसरों को महामारी से बचाने और इस अभियान को ज्यादा असरदार बनाने की है। लेकिन इस दौर से गुजर जाने के बाद की चुनौतियों के बारे में अभी से चिंतन शुरू करना चाहिए। पूरी दुनिया जिस नई त्रासदी के बारे में चिंतित है, वह है अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी के कारण बेरोजगारी की नई महामारी का संकट। भारत जैसे विकासशील देश में यह समस्या और भी ज्यादा गहरी है। करोड़ों प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार छिन चुका है। गांवों में उनके पास न तो आजीविका के साधन हैं, और न ही वे वहां लौटकर अपने शहरी हुनर का उपयोग कर सकते हैं। राजमिस्त्री, रिक्शा चालक, छोटे-छोटे घरेलू कल कारखानों में काम कर रहे मजदूर भला गांवों में लौटकर क्या कर पाएंगे? फिर से शहरों में जाकर रोजगार-धंधे कर पाना कम से कम साल-दो साल तक आसान नहीं होगा। हम जानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर उनके बच्चों पर पड़ेगा। जाहिर है कि स्कूल ड्रॉपआउट, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी और ट्रैफिकिंग आदि अपराध तेजी से बढ़ेंगे।

2. कोविद-19 महामारी के बाद नए प्रकार की राजनीति, अर्थ व्यवस्था और समाज की वह शक्ल नहीं रहेगी जो आज है। पहले भी प्राकृतिक आपदाओं और बड़े युद्धों के बाद इसी तरह की चीजें हुई हैं। लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अक्सर आपदाओं को युद्ध की तरह लड़कर जीतने की जन भावना बनाई जाती है। जनता अपने सेनापति पर भरोसा करती है, क्योंकि जिंदगी और नागरिक अधिकारों में से जिंदगी को चुनना स्वाभाविक है। उस वक्त डरा हुआ समाज यह भूल जाता है कि ये दोनों स्थितियां अलग-अलग हैं। आपदा प्रबंधन की कुशलता, संसाधन, सीधे तौर पर उससे जूझ रहे लोगों का समर्पण, त्याग व साहस और सामूहिक दया भाव त्रासदियों से निजात दिलाता है। जबकि युद्धों में सेनापति सर्वोच्च निर्णायक और शक्ति केन्द्र होता है। उसी का आदेश चलता है। सिर्फ वही बोलता है, बाकी सब सुनते और मानते हैं। इससे उलट, युद्ध की पद्धति से आपदा खत्म करने में असफल नेताओं के खिलाफ नागरिक कठोर फैसले ले सकने वाले मजबूत महानायक का विकल्प ढूंढ़ने लगते हैं। लोकतंत्र की अपनी सीमाएं और अंतर्विरोध होते हैं, इसलिए उसमें सुधार और विकास की गुंजाइश रहती है। आपदाओं को युद्ध की तरह लड़े जाने से उत्पन्न हुई सामूहिक मानसिकता के कारण थोड़े वक्त के लिए उपजा सुरक्षा या असुरक्षा और जीत अथवा हार का एहसास नागरिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान और मानव अधिकारों की जड़ों को कमजोर करता है।

3. आपदाओं के दौरान एक और सामान्य बात होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने गए नेता त्रासदी से निबटने की प्रक्रिया में भी अपने मतदाता आधार को ज्यादा प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। त्रासदी के बाद उनकी नजर अगले चुनाव पर टिकना स्वाभाविक बात है। ऐसी हालत में चुनावों पर खास असर न डाल सकने वाले सामाजिक और आर्थिक हासिये के बाहर रहने वाले लोग, जैसे वंचित वर्ग और उनके बच्चे, आर्थिक पुनर्निर्माण में भी वंचित रह जाते हैं। आदिवासी और आदिम समूह, विकलांग, घुमन्तू जन जातियां, देह व्यापार में लगे लोग, शरणार्थी व अप्रवासी समूह और फुटपाथों पर जीवनयापन करने वाले राजनैतिक लाभ के रडार के बाहर छूट जाते हैं, क्योंकि वे मुख्य धारा की राजनीति को प्रभावित नहीं करते।

4. त्रासदियों में केवल सत्ता की शक्ति का केन्द्रीकरण ही नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी का चरित्र भी बदलता है। जैसे युद्धों के बाद हथियारों की उन्नत तकनीक विकसित होती है, वैसे ही कोरोनावायरस की त्रासदी खत्म होने के बाद व्यक्तियों की निजता को नियंत्रित करने के लिए पहले से ज्यादा निर्लज्ज तरीके खोजे जाएंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगाकर कानूनों में बदलाव तक शामिल हैं। सत्ता के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के केन्द्रीकरण और अधिनायकवाद से नए प्रकार की राजनीति जन्मेगी। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़े जा रहे 'युद्ध' से कई लोकतांत्रिक देशों में उभरे महानायक अपने अनुयाईयों और समर्थकों के अलावा बड़ी तादाद में आम जनता के मन-मष्तिष्क पर भी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसी हालत में लोकतांत्रिक मूल्य और संस्थाओं का खतरे में पड़ना तय है।

5. पिछले कई सालों से भूमंडलीकरण सिर्फ व्यापार और मुनाफाखोरी तक सिमटकर रह गया था। तथाकथित इस्लामी आतंकवाद का हौआ, शरणार्थियों और विदेशी अप्रवासियों के प्रति बढ़ी असंवेदनशीलता, योरोप के कई देशों में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी आदि से उपजी अतिवादी राष्ट्रीय राजनीति के चलते भूमंडलीकरण के उद्देश्य की हत्या होती रही थी। अब तो उसका चरित्र ही बदल जाएगा। कोरोना की महामारी के बाद भावुक और उग्र राष्ट्रवाद बढ़ेगा, जिसका सबसे खतरनाक असर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कर्ज और व्यापार पर पड़ेगा। इस

बात का बहुत अंदेशा है कि ज्यादातर अफ्रीकी और एशियाई देशों में पहले से ही चीन का व्यापारिक और आर्थिक बोल-बाला था, वह और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा कई यूरोपीय देशों में चीन की निर्भरता, साख और पैठ बढ़ेगी। सहायता के रूप में दिये जाने वाले हरेक पैसे का अपना चरित्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में डॉलर, यूरो और पाउण्ड के मुकाबले युआन का चरित्र अलग होगा।

6. मानव सेवा, चैरिटी, दान और कल्याण की भावना उपयोगी है और जरूरी भी। परन्तु आपदाओं के गुजर जाने के बाद यह स्थाई नहीं रहती। अभी भी वर्ग भेद की मानसिकता साफ-साफ नजर आ रही है। उदाहरण के लिए भारत में जनता का मनोबल बढ़ाने और कोरोना से लड़ने वालों के लिए कृतज्ञता दर्शाने के लिए ताली और थाली का प्रयोग अच्छी बात थी, लेकिन ढोल-नगाड़े बजाते हुए सड़कों पर उतर कर भांगड़ा करते लोग किस वर्ग के थे? दीये जलने या और किसी तरह की रोशनी से मन को अच्छा लगता है। एकता भी नजर आती है, लेकिन सज-धज कर शर्मनाक आतिशबाजी करते हुए दीवाली मनाने वाला वर्ग कौन था? क्या यह उन करोड़ों लोगों के साथ भद्दा मजाक नहीं था जो न तो घर के रहे न घाट के। उनमें से लाखों अलग-अलग राज्यों में कैंपों में फंसे सरकारी या गैर सरकारी फूड पैकेटों के रहमों-करम पर रह कर गांव लौटने के इंतजार में तड़प रहे हैं।

भांगड़ा करने वालों में से भी बहुत से लोग उनपर दया करके खाना बांट रहे होंगे। लेकिन क्या उनके मन में सड़कों, मकानों, फ्लाइओवरों, स्कूलों, दुकानों, फैक्ट्रियों आदि के निर्माताओं, सफाई करने वाले और कई तरह की सुविधाएं देने वालों के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव है? शहरी इंडिया को बनाने वाला देहाती भारत कब अपनी इज्जत हासिल कर पाएगा? शहरी शान-ओ-शौकत और राष्ट्रीय जीडीपी को अपने कंधों पर ढोने वाले इतनी बड़ी तादाद में गांवों की तरफ क्यों भागे? क्योंकि इंडिया उन्हें आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक सुरक्षा तो दूर, उनका भरोसा तक नहीं दे सका। कृपा के बजाय कृतज्ञता का भाव ही समाज में समानता, न्याय और मानवीय गरिमा पैदा कर सकता है। पिछले दिनों कोरोना के खौफ के अलावा भारत की जो दुर्गति और बेइज्जती इंडिया ने की है, वह समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलोजी के हिसाब से एक असामान्य घटना है। इसका असर गरीबों की बेरोज़गारी और बर्बादी के अलावा गहरा अविश्वास, तनाव, चालाकी, आक्रोश और हिंसा की बढोत्तरी में होगा।

7. कार्पोरेट जगत को फिर से खड़ा होकर रफ्तार पकड़ने में बरसों लगेंगे। सरकारों के साथ गहरे रिश्ते रखने वाले चंद उद्योग घराने थोड़े कम वक्त में संभल जाएंगे। लम्बे समय के घोषित और अघोषित लॉकडाउन के अनुभव के बाद कार्पोरेट, सरकारी महकमें, शोध और शिक्षण से जुड़ी संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन आदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। घर से ही काम कराने की व्यावसायिक संस्कृति जरूर पनपेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट्स, आग्मेंटेड और वर्चुअल रियेलिटी, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के नए आयाम तो विकसित होंगे ही, रोबोटों और स्वचालित मशीनों की बाढ़ आ जाएगी। अभी भी हम कई देशों में देख रहे हैं कि चिकित्सा साधनों के अकाल की वजह से कोरोनावायरस से संक्रमित बूढ़े लोगों को बचाने के लिए नाम मात्र के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्पादक मानव संसाधन यानि युवाओं के बचाव पर ही ज्यादा जोर है। भविष्य में कर्मचारियों की तन्ख्वाहें, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा और दूसरी सहूलियतों पर पैसा खर्च करने के बजाय मशीनों तथा मशीनों को बनाने और चलाने वाले चंद व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्थिति शायद कुछ दशकों के बाद आती, वह बहुत जल्दी आ जाएगी।

8. इस महामारी के प्रकोप से अच्छा सबक सीखने के नाम पर यह भी संभव है कि पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कठोर उपाय किये जाएं। लेकिन जिस तरह का क्रूर औद्योगिक और उत्पादन तंत्र विकसित हो चुका है, उसके तौर-तरीके बदलना आसान नहीं हैं क्योंकि उसी व्यवस्था में ज्यादातर श्रमिकों को रोजगार मिलते हैं। बहुसंख्यक गरीबों को इंसानों की तरह जीने की बुनियादी साधनों के बजाय सुविधाएं, मौज-मस्ती, आडम्बर और भोग की सामग्री के उत्पादन से ज्यादा मुनाफा होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जब तक, मुट्ठी भर ही सही, संवेदनशील सरकारें और उद्योगपति अभूतपूर्व साहस तथा इनोवेशन के साथ अपने उत्पादनों का विकेन्द्रीकरण करके गांवों-देहातों में रोजगार पैदा नहीं करते, तब तक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता संभव नहीं है।

9. पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सकीय परामर्श की बाढ़ आ गई है। वह अभी तो मजबूरी लगती है, लेकिन यही अनुभव बहुत जल्दी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। आर्टिफिशिल इंटेलिजेंट्स और संचार तकनीकों के जरिये यह पद्धति बहुत सस्ती और आसान है। यहां मेरा इशारा सिर्फ शिक्षकों या चिकित्साकर्मियों की बेरोजगारी बढ़ने की तरफ ही नहीं है, बल्कि स्कूल भवनों, दवाखानों, धर्मस्थलों और बाजारों के बगैर चलने वाली जिंदगी की तरफ है। कुछ हफ्तों में ही हम महसूस कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा, हताशा, तनाव, पोर्नोग्राफी, मानसिक अवसाद आदि व्याधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। केवल स्क्रीन और माइक्रोफोन के माध्यम से मनुष्य जैसा सामाजिक प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श का धंधा खूब फलेगा-फूलेगा। नए-नए पाखंडी चमत्कारी गुरू पैदा होंगे। हम यह न भूलें कि प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से मिलकर वाद-विवाद व बातचीत करने, परामर्श करने, सवाल उठाने, दूसरों से अपनी व्यथा और खुशी साझा करने तथा सीखने और समझने की अनुभूति का कोई विकल्प नहीं है।

10. वैश्विक विकास की प्राथमिकताओं का बदलना तय है। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले तक आंतरिक और बाहरी युद्धों से पीड़ित लाखों शरणार्थियों की राहत और सुरक्षा बड़े मुद्दे नहीं थे। दो दशक पहले शुरू हुए आतंकवाद से पहले मानवीय सुरक्षा, विकास के दायरे में नहीं देखी जाती थी। विकास और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम आम तौर पर सरकारों की ही जिम्मेवारी थी। सिर्फ हाल के कुछ दशकों में कार्पोरेट जगत और सिविल सोसाईटी भी महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरे हैं। इस बात का बहुत अंदेशा है कि कोविद-19 प्रकोप के बाद सरकारों और उद्योग जगत के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनका मुकाबला करने में बच्चों की शिक्षा, स्वतंत्रता, चिकित्सा और सुरक्षा के मुद्दे पीछे रह जाएं। दुनियाभर में सीएसआर की फंडिंग का आकार और प्रकार भी बदलना सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी संस्थाओं की भूमिका, उपयोगिता और अस्तित्व तक में खतरे पड़ सकते हैं। इसी तरह की और भी चुनौतियां आ सकती हैं।

इससे एनजीओ क्षेत्र में आपसी खींचतान, प्रतिद्वंदिता और बिखराव बढ़ेगा। वे मानवाधिकारों पर आधारित व्यवस्थागत और नीतिगत बदलावों के लिए एडवोकेसी की जगह कल्याणकारी कामों की तरफ मुड़ेंगे। सरकारें भी इसी तरह के कानून बना सकती हैं।

हमारे आन्दोलन के साथियों को भी भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम भारत और दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विमर्श में शोषित और उत्पीड़ित बच्चों के मुद्दों को उठाए रखने में सबसे सक्षम हैं। मेरे विचार से इसके लिए कुछ काम करना बहुत जरूरी है।

पहला, कल ही हमारे सहयोगी संगठन आईसीपीएफ ने जो बेहद चैकाने वाला अध्ययन जारी किया है वह आपने पढ़ा होगा। देश में बढ़ रही चाइल्ड पोर्न की खपत बहुत खतरनाक संकेत है। आप इसका पूरा इस्तेमाल 'कीप चिल्ड्रेन सेफ ऐट होम' अभियान में करें। इसी तरह हमारे साथी चंदन जी, बिराज जी और निहारिका जी द्वारा लिखे गए लेखों को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें उतना अच्छा है।

दूसरा, हम अपने कामों, अनुभवों और उपलब्धियों पर पूरी आस्था रखते हुए उनका इस्तेमाल तर्कपूर्ण समाधानों के रूप में करें। दूसरा, अपने संपर्कों और संबंधों के दायरे को बढ़ाएं। अभी से यह काम सोशल मीडिया, टेलीफोनों आदि के माध्यम से किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकोप के बाद सामाजिक संगठनों, सरकारी विभागों, राजनेताओं, बाल अधिकार से संबंधित संस्थानों से मेल-मिलाप और तेज करें। हमें केवल मानवीय और नीतिगत तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस वैचारिक और आर्थिक तर्कों से हर जगह यह साबित करना पड़ेगा कि बाल मजदूरी तथा बच्चों के शोषण को खत्म किये बगैर गरीबी, बेरोजगारी आदि दूर नहीं किये जा सकते, और न ही आर्थिक व सामाजिक स्थायित्व तथा तरक्की संभव है।

तीसरा, आपको जब भी फुर्सत या सुविधा हो अपने साथियों और संगठन द्वारा किये जा रहे प्रयास को ट्विटर, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम आदि पर प्रसारित करें। आप बाल अधिकारों के क्षेत्र के सबसे बड़े चैम्पियन और नेतृत्वकर्ता हैं। यह आत्मगौरव आप सभी में बना रहना चाहिए।

हमारे आन्दोलन की मजबूती, शोषित और उत्पीड़न के शिकार बच्चों के मुद्दों को देश और दुनिया की मुख्य धारा में लाने का ये सबसे कारगर तरीका है।

मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में आपके निजी परिवार और मित्रों के अलावा पूरा का पूरा सत्यार्थी आन्दोलन आपका बड़ा परिवार है। आप में से किसी की भी कोई परेशानी को मैं अपनी परेशानी मानता हूं। आप लोगों के लिए मैं आन्दोलन का संस्थापक, प्रवर्तक या कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि आपके परिवार का मुखिया हूँ। इसी नाते मैं आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। कृपया अपने घर में सभी तक मेरा स्नेह पहुंचाएं। उनको और आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहना है।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ,

आपका

कैलाश सत्यार्थी